

अखंड भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज बुधवार 02 फरवरी 2022

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेंट

बजट
2022-2023
मिडिल क्लास निरुद्ध

यह अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करेगा। इस बजट से देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत व गति देने का काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और रोजगार पर बजट में जोर दिया गया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ये बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है। गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है। - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

जल जीवन मिशन को 60 हजार करोड़, 3.8 करोड़ घरों में पहुंचेगा नल से जल

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट में जलशक्ति मंत्रालय को जीवन जीवन मिशन-हर घर जल योजना को बढ़ा बजट मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वाली योजना "हर घर नल से जल" को बजट में 2022-23 के लिए 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे वित्त वर्ष 2022-23 में 3 करोड़ 80 लाख नए ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण की तरफ से पेश आत्मनिर्भर भारत का बजट 130 करोड़ भारतीयों को परिवर्तनकारी लाभ देगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि नल से जल के 3 करोड़ 80 लाख नए कनेक्शन, रासायनिक मुक्त कृषि के लिए गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़ा गलियारा से लेकर केन-बेटवा लिंक परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए पानी, यह सब सुनिश्चित करता है कि हर भारतीय की



जस्तुओं का बजट में पूरा करने का ध्यान रखा गया है। शत-प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुंचाने के वादे को पूरा करने की मजबूत कार्ययोजना प्रस्तुत करता है। परिवारों में से करीब 8 करोड़ 91 लाख से अधिक घरों में नल से जल मिलने लगा है। योजना की घोषणा के ढाई साल पूर्व 17 फीसदी से भी कम ग्रामीण घरों में नल से जल मिल रहा था। बजट में करीब 10 हजार करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में 3 करोड़ 25 लाख नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। संशोधित बजट अनुमान 45 हजार 11 करोड़ रुपये के मुकाबले तो यह करीब 15 हजार करोड़ रुपये अधिक है।

डिफेंस

● सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में स्वदेशी भागीदारी को महत्व दिया
● भविष्य में देश का रक्षा क्षेत्र घरेलू बाजार में तैयार होने वाले उपकरणों से लेस होगा



डिजिटल वर्ल्ड

● 5जी रोजगार के लिए सबसे बड़ा और उभरता हुआ सेक्टर, ग्रामीण इलाकों में सरसे इंटरनेट के लिए इंटरजाम किए जाएंगे
● जल्द ही जारी होंगे ई-पासपोर्ट, माइक्रो विप से होंगे लेस



एलआईसी

● भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का पहला पब्लिक आईपीओ जल्द आएगा कई अन्य सरकारी कंपनियों के भी आईपीओ जल्द आएंगे



कैसे क्या मिला

मिडिल क्लास

- आम आयकरदाताओं को बजट 2022 में कोई राहत नहीं
- 2.5 लाख रुपए की तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी
- अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख - 2.5 लाख = 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होगा
- 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होगा
- इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए का फायदा उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं

आवास

- गरीबों के लिए एक साल में बनाए जाएंगे 80 लाख मकान
- वित्त वर्ष 2022-23 में 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे

कृषि सेक्टर

- अब सीधे किसानों के खाते में जाएगी एमएसपी
- 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूँ और धान खरीदें जाएंगे
- एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजे जाएंगे
- जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा
- केन-बेटवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा
- स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करके किसानों को हार्डटैक बनाया जाएगा
- साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी

शिक्षा

- बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी और 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा
- डीटीएच प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना को 12 से 200 टीवी चैनल योजना तक बढ़ाया जाएगा
- मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।
- आदिवासी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी

स्वास्थ्य

- मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते देश में नेशनल टेलीमेंटल सेंटर शुरू किए जाएंगे

रेलवे

- अगले तीन सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी।
- रेलवे 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाएंगे
- किसानों के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना
- रफतार को नए आयाम देने की योजना 'पीएम गतिशक्ति'
- वंदे भारत: देश की सबसे तेज ट्रेन, इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा

महंगा-सस्ता ...

महंगा

कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट खत्म कर दिया गया है। इसपर 7.5 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया गया है। वहीं इमिग्रेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका कारण आयात को कम करना है। विदेशी छाता भी महंगा होगा। आयातित सामान महंगे होंगे। अक्टूबर से बिना ब्लॉकिंग वाले पयूल पर दो रुपये प्रति के लीटर के हिसाब से एक्ससाइज ड्यूटी लागू होगी है

सस्ता

कपड़ा, चमड़े का सामान, मोबाइल फोन, चार्जर, हीरे के आभूषण, खेती के सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा पॉलिस् हिरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसके अलावा विदेशी मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे।

जारी होगा डिजिटल रुपया, क्रिप्टो करेंसी पर देना होगा 30 फीसदी टैक्स

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में डिजिटल रुपये को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आरबीआई वित्त वर्ष 2022-23 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपये को रोलआउट करेगी। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक डिजिटल रुपये को ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी समेत कई अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। साधारण शब्दों में कहें, तो यह सरकारी वर्चुअल करेंसी होगी। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल रुपए को जारी किया जाएगा।



भारत की उम्मीदों का बजट

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट संसद में पेश कर दिया। सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट को डिजिटल फॉर्म में पेश करते हुये नौकरी, घर, किसान, रक्षा, व्यापार और क्रिप्टो सहित कई क्षेत्रों के लिये बड़े ऐलान किये। उन्होंने इस बजट को अगले 25 साल का

'ब्लू-प्रिंट' बताया है, जिसमें 60 लाख लोगों को नौकरी देने की भी घोषणा की। वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में सबसे ज्यादा इंतजार आयकर में बदलाव का था, लेकिन मध्यम वर्ग को वित्त मंत्री सीतारमण के इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है। आयकर स्लेब में इस वर्ष भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक

(आरबीआई) इस वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा, जिस पर होने वाली कमाई पर 30 फीसदी का कर लगेगा। निर्मला सीतारमण ने साल 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद लगातार चौथी बार बजट पेश कर रही थीं। सीतारमण के बजट भाषण के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि वित्त मंत्री जी

डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है, यह व्यय जीडीपी का 2.9 फीसदी होगा। इसके साथ ही कटे एवं पॉलिश हीरे और रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5 फीसदी करने की घोषणा भी की। सीतारमण ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल

एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। बजट पेश करते हुये निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवोजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के साथ एक एवोजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स

का गठन किया जाएगा, जो हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिये घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी। इसके साथ ही ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, जिसे आरबीआई वित्त वर्ष 2022-23 में जारी करेगा। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना

के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिये 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने का ऐलान किया। इसके साथ ही आम बजट 2022-23 के लिये 7.5 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का भी प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.9 फीसदी होगा।

